वर्ष :-1

अंक:-284

25.11.2025

मंगलवार

अपना शहर अपना खबर

अपना नालन्दा

 नालंदा का नंबर वन डिजिटल अखबार www.apnanalanda.com

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कई इकाइयों का निरीक्षण किया

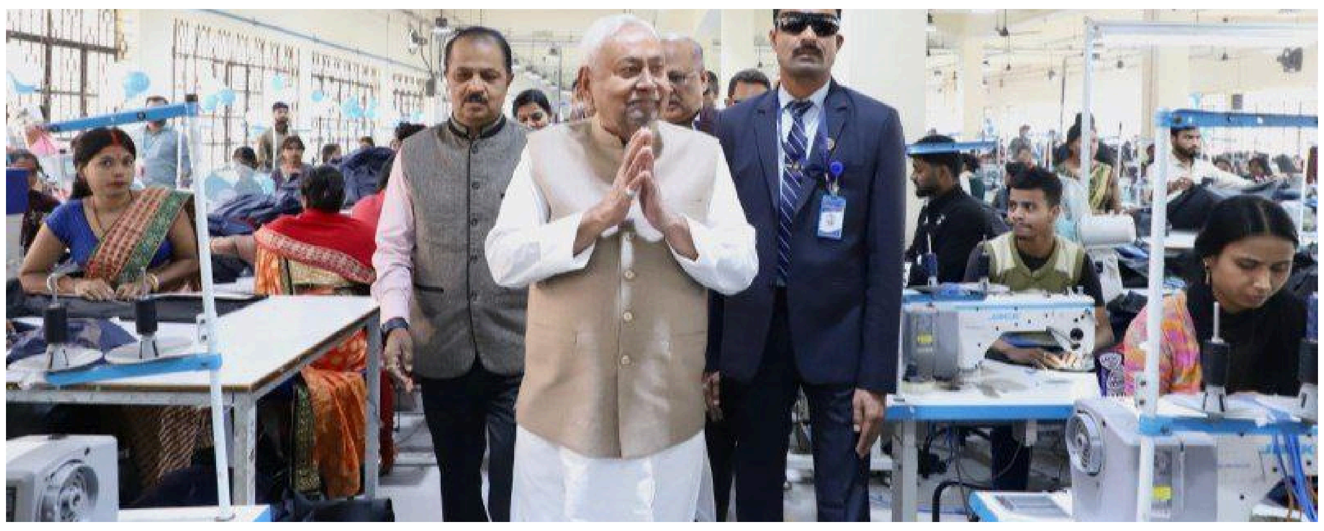

सुजीत कुमार

पटना (अपना नालंदा)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर उत्पादन, प्रबंधन और निर्यात गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने न्यू ज़ील सीज़नल वियर प्राइवेट लिमिटेड से की, जहाँ रेन वियर का निर्माण किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि यहां लगभग 650 लोग कार्यरत हैं, जिनमें 95 प्रतिशत स्थानीय महिलाएं हैं।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने कॉम्पीटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया। उन्होंने जूतों एवं बूट निर्माण से जुड़े प्रक्रमों की जानकारी ली। बताया गया कि इस इकाई में निर्मित जूते रूस, स्पेन और इंग्लैंड सहित कई देशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे यह उद्योग क्षेत्र का एक प्रमुख निर्यात केंद्र बन चुका है।मुख्यमंत्री ने ब्रिटानियाइंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्लांट का भी निरीक्षण किया, जहाँ बिस्कुट और कुकीज़ का उत्पादन होता है तथा इनका निर्यात भी किया जाता है। उन्होंने अनमोल इंडस्ट्रीज़ द्वारा निर्मित बिस्कुट और नमकीन उत्पादों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की।हाजीपुर औद्योगिक क्लस्टर में कुल 9 औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें 289 औद्योगिक इकाइयों को 291.83 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है, जबकि 304.11 एकड़ भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है। क्लस्टर में 11 केवी और 33 केवी विद्युत आपूर्ति, मजबूत सड़क नेटवर्क, सोलर स्ट्रीट लाइट, जल निकासी प्रणाली, बाउंड्री वॉल और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पत्तों पर नक्काशी से धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि

पटना (अपना नालंदा)। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सैंड एवं लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर अपनी विशिष्ट कला के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। कलाकार ने पीपल के पत्ते पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी कर धर्मेंद्र की एक यादगार प्रतिमा का निर्माण किया है। इस कलाकृति पर "हमसे ना टकराना" और "अलविदा ही-मैन धरम पाजी" लिखकर उन्होंने अभिनेता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।मधुरेंद्र कुमार, जो अपनी लघु नक्काशी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने वाली लीफ आर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं, ने बताया कि धर्मेंद्र साहब भारतीय सिनेमा के ऐसे सितारे थे जिन्होंनेअपने दमदार अभिनय, गंभीर संवाद अदायगी और सहज व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने कहा कि यह कलाकृति उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का एक विनम्र प्रयास है, क्योंकि ऐसे महान कलाकार विरले ही जन्म लेते हैं। धर्मेंद्र के निधन से फिल्म जगत और उनके चाहने वालों में शोक की गहरी लहर है। इसी बीच मधुरेंद्र द्वारा बनाई गई यह अनोखी कलाकृति सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस अनूठी श्रद्धांजलि की प्रशंसा कर रहे हैं और इसे अभिनेता की स्मृति को जीवित रखने वाला एक भावुक प्रयास बता रहे हैं।कलाकार ने कहा कि महान व्यक्तित्व कभी समाप्त नहीं होते; उनकी कला, उनके विचार और उनका योगदान उन्हें समय की धारा में हमेशा जीवित रखता है।

शिवनंदन नगर हटाने के नोटिस के खिलाफ भाकपा का समाहरणालय पर उग्र विरोध प्रदर्शन

संजय कुमार

बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। रहुई अंचलाधिकारी द्वारा शिवनंदन नगर के 120 भूमिहीन परिवारों को 26 नवंबर तक घर खाली करने का निर्देश दिए जाने के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने सोमवार को समाहरणालय मुख्य द्वार पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय के मुख्य गेट को घेरते हुए सड़क जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आंदोलन का नेतृत्व भाकपा के वरिष्ठ नेता शिव कुमार यादव ने किया।भाकपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के नोटिस को अन्यायपूर्ण बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। बाद में जिलाधिकारी के साथ सकारात्मक वार्ता होने पर सड़क जाम हटा लिया गया।मामला मौजा सोनसा, थाना संख्या 16 के खाता नंबर 198, खेसरा नंबर 1616 के गैरमजरूआ आम पोखर की भूमि से जुड़ा है, जहाँ वर्षों से अनुसूचित जाति के 120 भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय और इंदिरा आवास की सुविधा दी गई है। कई परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई से पक्का घर भी बनाया है।भाकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय दबंग जाति और कुछ राजनीतिक तत्वों के दबाव में प्रशासन न्यायालय के आदेशों और सरकारी संकल्प की अनदेखी कर रहा है।22 नवंबर को बिहार के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया था कि उच्च न्यायालय ने अपने 19 अप्रैल 2023 के आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के भूमिहीन परिवारों को पहले बिहार सरकार के नियम के अनुसार कम से कम 20 के समूह (क्लस्टर) में प्रत्येक को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए, तभी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इसके उलट प्रशासन ने 3 डिसमिल और 2 डिसमिल के छोटे-छोटे प्लॉट देकर पर्चा जारी कर दिया है, जो न उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप है और न ही सरकार की घोषित नीति के मुताबिक। उन्होंने कहा कि प्रशासन मनमाने ढंग से हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि कई प्रस्तावित पर्चों पर स्वत्व वाद भी अदालत में लंबित है।नेताओं ने यह भी कहा कि जमीन विवाद में याचिका दायर करने वाला सीताराम प्रसाद और उसके समर्थक स्वयं 294 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिस पर प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है।

प्रदर्शन में राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रभात कुमार पांडेय, जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद, सत्येंद्र कृष्ण, रामप्रवेश सिंह, सकलदेव यादव, रामनरेश पंडित, सुरेश प्रसाद सिंह, उमेश चंद्र चौधरी, बीके पासवान, पवन कुमार, फूल देवी, राजकुमारी देवी, नरेंद्र पासवान, गुड्डू पासवान, राजन पंडित सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए।भाकपा ने चेतावनी दी कि यदि 26 नवंबर का नोटिस वापस नहीं लिया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा।

SAI BODHIT PVT. LTD.
बिहारशरीफ़ की नई पहचान
SHRIEJAN HEIGHTS में अपना आशियाना।
SHRIEJAN HEIGHTS
कल्पना एक सुंदर-समृद्ध भारत की।
LIFESTYLE OF THE WORLD COMES TO BIHARSHARIF
चोरा बगीचा से केवल 2 मिनट की दुरी पर ....
APPROVED RERA APPROVED APPROVED
"BOOKINGS ARE NOW OPEN !"
BOOK 3BHK PREMIUM FLAT
Project Registration Number
BRERAP192001011025250432E00
₹ 4251/*SQ.FT.
60% Free Area
COMFORT, LUXURY WELLNESS
Amenities
• Swimming Pool
• Vastu Compliant Design
• Kids' Play Area
• Volleyball / Badminton Court
• Cricket net pitch
• Landscape & Roof Top Garden
• Temple in Premises
• Highly Secured Society (24x7 security & cctv surveillance)
• 100% Power Backup
• Ample Parking Space & Visitor Car Parking Facility
• EV Reserved Car Parking
Site/Office -
सृजन कोल्ड स्टोरेज,
नालंदा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सामने,
राजगीर रोड, बिहारशरीफ (4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग-82)
Contact Us -
1800 5728 177 (TOLL FREE NUMBER)
9031605004, 7280027960
60018 06049, 96615 74892
Contact us today to book your site visit!

28 नवंबर को लोजपा रामविलास मनाएगी स्थापना दिवस, तैयारियां तेज

सुजीत कुमार

पटना (अपना नालंदा)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश कार्यालय, 1 व्हीलर रोड पटना में सोमवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक राजू तिवारी ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आगामी 28 नवंबर को पटना स्थित बापू सभागार में पार्टी का 25वां स्थापना दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाएगा।इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। श्री तिवारी ने कहा कि यह समारोह पार्टी के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी नेता, समर्पित कार्यकर्ता तथा बिहार से जुड़े सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।उन्होंने बताया कि समारोह में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और बिहार सरकार में शामिल लोजपा (रामविलास) के मंत्रियों का विशेष रूप से अभिनंदन किया जाएगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव, सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में समर्पित कार्यकर्ता भाग लेंगे।प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के अलावा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी, संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे, मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट और युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे उपस्थित थे। सभी नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी किए जाने की जानकारी दी।

बिहार में 11 सैटेलाइट सिटी विकसित करने की योजना पर विभाग की सहमति

सुजीत कुमार

पटना (अपना नालंदा)। नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रभार ग्रहण करने के बाद मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने जो विश्वास उन्हें सौंपा है, वह उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में विभाग का मुख्य लक्ष्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को सुचारु, सुव्यवस्थित और सुंदर बनाना रहेगा।मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार में 11 सैटेलाइट सिटी विकसित किए जाने की योजना पर विभाग ने सहमति दे दी है। इनमें नौ कमिश्नरी शहरों के साथ-साथ सीतामढ़ी और पटना के सोनपुर को सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन नए शहरों में सड़कें, पार्क, खेल मैदान, सामुदायिक केंद्र सहित आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा। यह योजना बड़े शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी।उन्होंने कहा कि राज्य में शहरीकरण की दर को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाना लक्ष्य है। इसके लिए जल निकासी, यातायात प्रबंधन, कचरा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था और आधारभूत संरचना सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, स्मार्ट शहर परियोजनाओं का विस्तार, स्वच्छता अभियान को गति और पेयजल आपूर्ति में सुधार को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

आवास क्षेत्र में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता होगी। मंत्री ने कहा कि शहरी परिवहन को सुगम करने के लिए नए मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और अतिक्रमण हटाने की ठोस रणनीति लागू की जाएगी।उन्होंने भरोसा जताया कि विकासशील नीतियों और जनता के सहयोग से बिहार शहरी प्रबंधन और आवास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।

राजीव नगर नाले पर फोरलेन सड़क निर्माण की शुरुआत, विधायक ने किया शुभारंभ

सुजीत कुमार

पटना (अपना नालंदा)। राजीव नगर से कुर्जी तक खुले नाले को पाटकर फोरलेन सड़क बनाने की बहुप्रतीक्षित परियोजना का कार्य सोमवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गया। राजीव नगर रोड संख्या 0 के पास आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने नारियल फोड़कर तथा पोकलेन मशीन चलाकर 181 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना का शुभारंभ किया।

विधायक चौरसिया ने बताया कि फोरलेन सड़क बन जाने से राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, केसरी नगर, एजी कॉलोनी, कौटिल्य नगर, सीडीए कॉलोनी, पटेल नगर, इंद्रा नगर, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया और कुर्जी सहित आसपास के मोहल्लों के लगभग दो लाख लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सड़क वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान देगी और पूरे क्षेत्र की सूरत अगले दो वर्षों में बदल जाएगी।उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों के भीतर बाबा चौक से अटल पथ होते हुए राजापुर पुल तक के नाले को पाटने का काम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त करवाने हेतु उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, नगर विकास एवं आवास मंत्री तथा बुडको के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी की प्रगति यात्रा के दौरान राजीव नगर एवं बाबा चौक नाले का निरीक्षण कर बुडको को जल्द कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया था।

भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने देवघर-बासुकीनाथ में की पूजा-अर्चना

सुजीत कुमार

पटना (अपना नालंदा)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार सरकार में उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल सोमवार को सपरिवार झारखंड के देवघर पहुंचे, जहाँ उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर बिहारवासियों की खुशहाली, आरोग्य, समृद्धि और मंगलकामनाओं के लिए आशीर्वाद मांगा।

पूजा के उपरांत डॉ. जायसवाल ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद जन-सेवा और राज्य के समग्र विकास के संकल्प को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति काअनुपम अनुभव बताया।देवघर दर्शन के बाद वे दुमका के बासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहाँ उन्होंने पुनः पूजा-अर्चना कर बिहार के लोगोंके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने की प्रार्थना की। उद्योग मंत्री ने कहा कि बाबा की कृपा से हृदय में दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और दृढ़ बनाती है।डॉ. जायसवाल ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह स्थल धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही पर्यटन के लिए भी आकर्षक है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपनी आस्था और परंपराओं को बनाए रखने की अपील की।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह देवघर-बासुकीनाथ दौरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ राज्यवासियों के कल्याण और विकास के प्रति उनके संकल्प का प्रतीक माना जा रहा है।

देकपुरा विद्यालय बेंच-डेस्क घोटाला: लिपिक पर कार्रवाई, जांच रिपोर्ट लंबित

अखिलेंद्र कुमार

बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। उत्क्रमित मध्य विद्यालय देकपुरा, रहुई में बेंच-डेस्क आपूर्ति में हुई गंभीर अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन लिपिक अजय कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई जारी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) नालंदा द्वारा उपलब्ध कराए गए आरोप पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि विद्यालय में 117 सेट बेंच-डेस्क की आपूर्ति किए बिना ही भुगतान कर दिया गया था। इस मामले में बिहार सरकारी सेवक नियमावली-1976 के नियम 19(6) के तहत लिपिक अजय कुमार को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखा गया है।

जांच में यह पाया गया कि विद्यालय को सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, फिर भी मेसर्स लता इंटरप्राइजेज, हेरिटेज सिटी, नालंदा को ₹5,83,830 (पाँच लाख तिरासी हजार आठ सौ तीस रुपये) की राशि का भुगतान कर दिया गया। इस अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन लिपिक पर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय की गई है।मामले की जांच हेतु प्रपत्र 'क' गठित करते हुए डीईओ रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) नालंदा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्देश दिया गया था कि 45 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन जमा कर दिया जाए, परंतु निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।इस पर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, पटना ने पुनः निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। देरी के मामले में संबंधित पदाधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा।

बादी मुशहरी स्कूल में मध्याह्न भोजन सामग्री चोरी से हड़कंप मचा

आर संतोष भारती

कतरीसराय (अपना नालंदा)। बादी मुशहरी प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन की सामग्री चोरी हो जाने से विद्यालय प्रशासन एवं ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कार्यवाहक प्रभारी शिक्षिका रजनी कुमारी ने बताया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक टुन्नी कुमार आकस्मिक अवकाश पर हैं, ऐसे में विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी उन पर है। सोमवार की सुबह जब वह निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि कार्यालय कक्ष और रसोईघर का ताला टूटा हुआ है। तत्काल जानकारी उन्होंने प्रभारी प्रधानाध्यापक को दी, जो मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने विद्यालय परिसर में रखी मध्याह्न भोजन योजना की भारी मात्रा में सामग्री चोरी कर ली। चोर 14 बोरा चावल, 5किलो दाल, 2 किलो तेल, एक भरा गैस सिलेंडर, दो बड़ा टब, एक स्टील और एक एल्यूमिनियम का बर्तन सहित अन्य आवश्यक सामग्री उठा ले गए। शिक्षिका ने बताया कि सुबह स्कूल का ताला टूटा पाया गया और सभी खाद्यान्न व रसोई से जुड़े उपकरण गायब थे। घटना की जानकारी लिखित रूप से स्थानीय प्रशासन व पुलिस को दे दी गई है।थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में जुट गई है तथा आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की जा रही है। इधर, ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से स्कूल परिसर में सुरक्षा मजबूत करने की मांग की है। चोरी की इस घटना से मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित होने की संभावना है। शिक्षकों ने जल्द सामग्री उपलब्ध कराने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

पूर्व सीजेआई गवई के क्रीमी लेयर बयान के गहरे न्यायिक और सियासी निहितार्थ

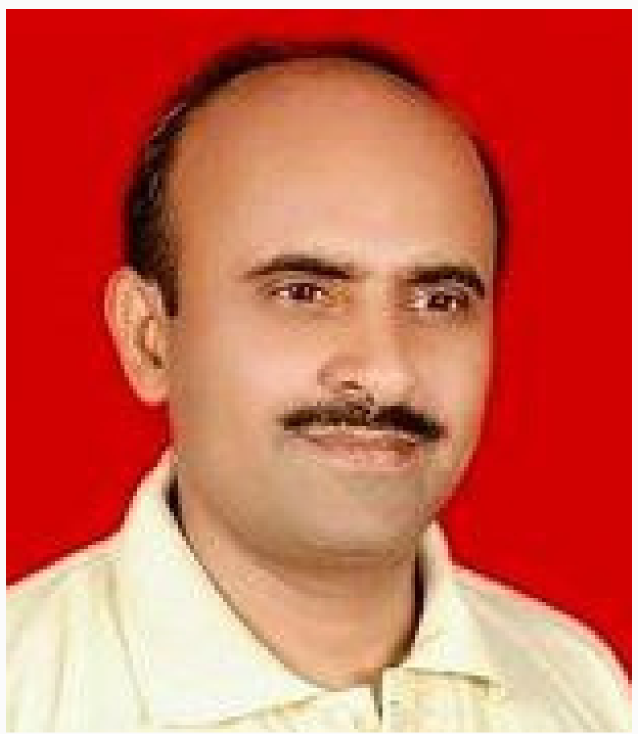

कमलेश पांडेय

अल्पसंख्यक 'दलित बौद्ध' सम्प्रदाय से आने वाले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई जाते-जाते एक नया वैचारिक-वैधानिक विचार विस्फोट कर गए जिसके दूरगामी न्यायिक और सियासी असर होंगे, इसलिए इसके कुछेक मायने अहम हैं। बताते चलें कि फॉर्मर चीफ जस्टिस गवई ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का गत रविवार को पुरजोर बचाव किया, साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) कोटा से क्रीमी लेयर यानी संपन्न लोगों को बाहर रखने का समर्थन किया। वहीं, शीर्ष अदालत में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने पर खेद व्यक्त किया।

दरअसल, अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के जागरूक पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में 52वें प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि वह संस्था को "पूर्ण संतुष्टि और संतोष की भावना के साथ" छोड़ रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी कार्यभार स्वीकार नहीं करने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वह पहले बौद्ध सीजेआई होने के अलावा के. जी. बालकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित हैं। इसलिए जाते जाते उन्होंने जो कुछ भी टिप्पणी की है, उससे निकट भविष्य में न्यायपालिका और सियासत दोनों के प्रभावित होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। जब निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने यह कहा कि, "मैंने पदभार ग्रहण करते समय ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी आधिकारिक कार्यभार स्वीकार नहीं करूंगा। अगले 9 से 10 दिन 'कूलिंग ऑफ' अवधि है। उसके बाद एक नयी पारी शुरू करूँगा।" # सीजेआई गवई ने एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने के वकालत की भी बात कही

सीजेआई गवई ने एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने के वकालत की। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत के लागू होने और एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर के लागूनहीं हो पाने की सियासी वजहों और व्यक्तिगत न्यायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह खुद एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करने के पक्षधर हैं। इससे जरूरतमंदों को फायदा पहुंचेगा।

मसलन, अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आरक्षण से जुड़े उस महत्वपूर्ण मामले को उठाया, जिस पर वह बोलते रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) में भी क्रीमीलेयर लागू करने की वकालत की। देखा जाए तो चीफ जस्टिस गवई ने इस मुद्दे से जुड़े जिन पहलुओं को उठाया, वे अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और हमारे राजनीतिक नेतृत्व द्वारा उन पर गम्भीरता पूर्वक गौर किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों के संपन्न लोगों को आरक्षण के लाभों से वंचित करने के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू करने पर अपने विचारों का पुरज़ोर बचाव करते हुए उन्होंने कहा, "अगर ये लाभ बार-बार एक ही परिवार को मिलते रहेंगे, तो वर्ग के भीतर वर्ग उभर आएगा। आरक्षण उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सचमुच ज़रूरत है।" उन्होंने सवाल किया, "अगर किसी मुख्य सचिव के बेटे या गांव में काम करने वाले भूमिहीन मज़दूर के बच्चे को... किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी के बेटे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़े... तो क्या यह समान स्तर पर होगा?" न्यायमूर्ति गवई ने आगाह किया कि इस तरह के कदम उठाये बिना, आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवारों द्वारा हथिया लिया जाता है जिससे "वर्ग के भीतर वर्ग" का निर्माण होता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय "सरकार और संसद को लेना है।" आरक्षण के जनहितकारी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि रिजर्वेशन उसी को मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है। क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करना है लेकिन पिछड़े वर्गों के भीतर भी जो आगे बढ़ चुके हैं, उन्हे हमेशा के लिए यह लाभ नहीं मिलना चाहिए।

कहना न होगा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर का सवाल बहुत ही पुराना मुद्दा है यानी क्रीमीलेयर का सवाल बिल्कुल नया नहीं है बल्कि तमिलनाडु सरकार ने 1969 में पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सत्तनाथन कमिशन का गठन किया था जिसने क्रीमीलेयर का कॉन्सेप्ट पेश किया। वहीं, 1986 में कर्नाटक सरकार से जुड़े एक मुकदमे में शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार को आर्थिक आधार पर जांच लागू करनी चाहिए ताकि सही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके।

यही वजह है कि सीजेआई ने क्रीमी लेयर के मसले पर अपनी दो टूक राय रखी क्योंकि यह ओबीसी आरक्षण में पहले से ही लागू है। इस मामले में इंदिरा साहनी बनामभारत संघ का मुकदमा नजीर बन चुका है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रखने और ओबीसी में क्रीमीलेयर लागू करने का फैसला दिया था। इसके बाद केंद्र ने एक आयोग गठित किया ताकि क्रीमीलेयर परिभाषित हो सके।

सवाल है कि जब एक वर्ग में प्रशासनिक क्राइटेरिया तय है तो इसे दूसरे वर्गों में भी आजमाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ताकि सभी तक फायदा पहुंचे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त 2024 में ही एससी-एसटी कैटिगरी के भीतर सब-कैटिगरी को मंजूरी दी थी। इसका मकसद यही था कि वर्ग के भीतर मौजूद हर जाति तक आरक्षण का फायदा पहुंचे और कोई खास तबका ही लाभान्वित न होता रहे।

सच कहा जाए तो क्रीमीलेयर भी इसी मकसद के लिए जरूरी है। 50 साल पहले जस्टिस कृष्ण अय्यर ने आरक्षण की इसी खामी की ओर ध्यान दिलाया था कि चूंकि समाज का ऊपरी तबका सारे लाभ ले जाता है। इसलिए सभी के लिए मौका सुनिश्चित करने की संसदीय पहल अविलंब शुरू की जानी चाहिए। इस अहम मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।

चूंकि पूरे देश में इस समय आरक्षण की सीमा को लेकर चर्चा है। यह एक बड़ी मांग है कि 50 प्रतिशत लिमिट नहीं होनी चाहिए लेकिन, अगर जरूरतमंदों को फायदा नहीं मिल रहा तो कोई भी लिमिट आरक्षण के उद्देश्य को पूरा नही कर सकती है। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुके है, उन्हें दूसरों का रास्ता रोकने के बजाय, आगे से हटकर पीछे वालों को रास्ता देना चाहिए। आखिर सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, न्यायधीशों के पुत्र-पुत्रियां या उनके आश्रित जब पुनः आरक्षण का लाभ लेते हैं तो यह आरक्षण के सिद्धांत का दुरुपयोग है।

विगत लगभग 8 दशकों से जारी इस पक्षपात पर खामोश विधायिका को अब कठघरे में खड़ा करने का वक्त आ गया है। इस पर कुतर्क गढ़ रहे बुद्धिजीवियों की नकेल भी कसनी चाहिए। इसी में भारतीय समाज का हित निहित है। तभी तो अपने कार्यकाल के अंतिम दिन न्यायमूर्ति गवई ने लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, जिनमें जूता फेंके जाने की घटना, लंबित मामले, राष्ट्रपति के राय मांगे जाने पर उनके फैसले की आलोचना, अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने पर उनके विवादास्पद विचार तथा उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व शामिल थे।

सीजेआई गवई ने कॉलेजियम प्रणाली का पुरजोर बचाव किया

वहीं, कॉलेजियम प्रणाली का पुरजोर बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यह "न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने" में मदद करती है। यह स्वीकार करते हुए कि कोई भी व्यवस्था पूर्णतः परिपूर्ण नहीं होती, उन्होंने कहा कि यह न्यायाधीशों के "चयन के लिए बेहतर है" क्योंकि वकील "प्रधानमंत्री या कानून मंत्री के सामने आकर बहस नहीं करते।" उन्होंने कहा, "इस बात की आलोचना होती है कि न्यायाधीश स्वयं नियुक्ति करते हैं। लेकिन इससे स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। हम खुफिया ब्यूरो की जानकारी और सरकार के विचारों पर भी राय जाहिर करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कॉलेजियम का होता है।"

वहीं, विधेयकों पर राज्यपालों के निर्णयों से जुड़ी समय-सीमा के मुद्दे पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "संविधान न्यायालय को ऐसी समय-सीमा की व्याख्या करने की अनुमति नहीं देता जहां कोई समय-सीमा मौजूद ही न हो। लेकिन हमने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते। अत्यधिक विलंब होने पर न्यायिक समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है।" उन्होंने "शक्तियों के पृथक्करण" का हवाला दिया और कहा कि जबकि राज्यपाल "अंतहीन समय तक विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते" और सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है, न्यायपालिका संविधान में कुछ ऐसी व्याख्या नहीं कर सकती जो संविधान में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि राजनीतिक कार्यकर्ता रामकृष्ण एस. गवई के पुत्र, न्यायमूर्ति गवई ने सामाजिक कार्य शुरू करने के बारे में कहा कि यह "उनके खून में" है और वह अपने गृह जिले अमरावती में आदिवासी कल्याण के लिए काम करते हुए समय बिताना चाहते हैं। वहीं, लंबित मामलों को एक "बड़ी समस्या" बताते हुए, उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में शीर्ष अदालत ने मामलों को श्रेणीबद्ध किये जाने और वर्गीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग शुरू किया और इससे निपटना "सर्वोच्च प्राथमिकता" होनी चाहिए।

निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान शीर्ष न्यायालय में महिला न्यायाधीश की नियुक्ति न कर पाने पर खेद व्यक्त किया लेकिन स्पष्ट किया कि ऐसा प्रतिबद्धता की कमी के कारण नहीं हुआ। उन्होंने कहा, "कॉलेजियम के फैसलों में कम से कम चार न्यायाधीशों की सहमति जरूरी है। आम सहमति जरूरी है। ऐसा कोई नाम नहीं आया जिसे कॉलेजियम सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे सके।"

फिर न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की लिखित असहमति के बारे में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, "ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर असहमति में कोई दम होता तो उस पर चार अन्य न्यायाधीशों को भी सहमत होना चाहिए।"

विश्वसनीयता विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है

राजेश कुमार पासी

बिहार में करारी हार विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। वो यह मानने को तैयार नहीं है कि 20 साल के शासन के बाद भी नीतीश कुमार को जनता बदलने को तैयार नहीं है। वास्तव में जनता को कोई भी खुश नहीं कर सकता और ये बात जनता भी जानती है कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर सकता। भारत की जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो सिर्फ बदलाव लाने के लिए ही वोट नहीं देती है। वो बदलाव लाने से पहले यह देखती है कि उसके सामने जो विकल्प है, क्या वो वर्तमान नेता या राजनीतिक दल से बेहतर है। नीतीश कुमार के विरोधी यह तो जानते हैं कि उनके प्रति जनता में नाराजगी है लेकिन वो यह नहीं देख पाते कि उनका विकल्प आज भी बिहार की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा में ऐसा नेता बन नहीं पाया है, इसलिए भाजपा भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को बदलने के लिए उचित समय का इंतजार कर रही है।

भाजपा नेतृत्व हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है, इसलिए उससे बहुत कम गलतियां होती हैं। विपक्ष जनता से कट चुका है,इसलिए वो जमीनी हकीकत से दूर रहता है। वो अपनी रैलियों और रोड शो में आई भीड़ से ही अपनी जीत का अंदाजा लगा लेता है। भारत का विपक्ष इतना ज्यादा आलसी हो गया है कि वो इसी उम्मीद के साथ चुनाव में उतरता है कि जनता वर्तमान सत्ता से नाराज है, इसलिए बिना कुछ करे ही उसकी जीत होने वाली है। विपक्ष भी पूरी तरह से गलत नहीं है क्योंकि पहले राजनीति में यह रिवायत बन चुकी थी कि जनता बेशक सत्ता से खुश हो, इसके बावजूद वो सत्ता परिवर्तन कर देती थी। जनता दो प्रमुख दलों में सत्ता की अदलाबदली करती रहती थी। अब ये रिवायत खत्म हो चुकी है, अब जनता तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं करती जब तक कि वो वर्तमान सत्ता से ज्यादा नाराज न हो। कांग्रेस ने केंद्र में दस साल तक लगातार शासन किया और अब भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ऐसे ही गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल और कई राज्यों में लगातार एक ही पार्टी की सरकार चल रही है।

भारतीय राजनीति पिछले 15-20 सालों में बहुत बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने लोकलुभावन वादे करके पहले दिल्ली और फिर पंजाब में सत्ता हासिल कर ली। ऐसा लगा कि लोकलुभावन वादे सत्ता हासिल करने का बहुत आसान रास्ता है। आम आदमी पार्टी ने इस रास्ते पर चलकर अन्य कई राज्यों में चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि सिर्फ लोकलुभावन वादे करके सत्ता हासिल करना संभव नहीं है, इसके लिए राजनीतिक दल की विश्वसनीयता और अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां भी होनी चाहिए। बिहार में महागठबंधन ने एनडीए से कहीं ज्यादा लोकलुभावन वादे किये थे, लेकिन उसे शर्मनाक हार मिली। विपक्ष की विश्वसनीयता जनता में लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि वो सिर्फ भाजपा और उसके सहयोगी दलों की बुराइयों का ढिंढोरा पीटकर वोट पाने की उम्मीद में रहता है। देश की गरीबी, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों की बात करता है लेकिन देश की समस्याओं का उसके पास क्या समाधान है, ये नहीं बताता है।

बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने वादा किया कि वो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन कैसे देंगे, ये उन्हें पता नहीं था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया कि हर महिला को एक लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे, लेकिन कैसे दिए जाएंगे, ये कांग्रेस बता नहीं सकी। देखा जाए तो दोनों ही वादे इतने आकर्षक हैं कि विपक्ष को तीन चौथाई से भी बड़ा बहुमत दिला सकते थे लेकिन इतने बड़े वादे करने के बाद बिहार में महागठबंधन धराशायी हो गया। लोकसभा में कांग्रेस को जरूर उसके वादे का कुछ राज्यों में फायदा हुआ लेकिन उसकी कुछ दूसरी वजह भी थी। नीतीश सरकार पर आरोप लगाया गया कि उसने एक करोड़ महिलाओं को दस हजार की रिश्वत देकर चुनाव जीत लिया लेकिन तेजस्वी यादव ने तो सरकार बनते ही तीस हजार देने की बात कही, क्या वो रिश्वत नहीं थी। नीतीश कुमार तो दस हजार दे चुके थे, लेकिन तेजस्वी यादव तो देने वाले थे। इस तरह देखा जाए तो महिलाओं को ज्यादा फायदा तो तेजस्वी यादव को वोट देने से मिलने वाला था। बच्चों को सरकारी नौकरी मिलना तो बिहार की महिलाओं के लिए सबसे सुनहरा सपना है लेकिन महिलाओं ने उस सपने के पीछे जाना पसंद नहीं किया। सवाल यह है कि क्या महिलाएं नहीं चाहती हैं कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। सच तो यह है कि बिहार में हर महिला का ये सपना हो सकता है लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि ये सपना तेजस्वी यादव पूरा कर सकते हैं।

मोदी के कट्टर आलोचक और भाजपा के कट्टर विरोधी योगेंद्र यादव कहते हैं कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक बातें करता है जबकि मोदी की बातों में 80% बातें सकारात्मक होती हैं। वो हैरानी जताते हुए कहते हैं कि विपक्ष को देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखता है। वैसे देखा जाए तो योगेंद्र यादव के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि उन्हें भाजपा और मोदी में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। बिहार में उनके सारे आंकलन धरे रह गए तो उनके मुंह से कुछ सच बाहर निकल आया। वास्तव में योगेंद्र यादव जैसे लोग भी विपक्ष की बड़ी कमजोरी हैं, जो विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। आज योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एसआईआर कोईचुनावी मुद्दा ही नहीं था, उस पर विपक्ष को मेहनत नहीं करनी चाहिए थी लेकिन चुनाव से पहले उन्हें यह बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा था।

कांग्रेस को खुद से ही एक बात सीखने की जरूरत है कि वो क्यों गांधी परिवार की गुलाम बन कर रह गई है। क्यों राहुल गांधी के बार-बार असफल होने के बावजूद वो उनके पीछे चल रही है। कांग्रेस जानती है कि गांधी परिवार उसकी मजबूरी है, अगर गांधी परिवार कांग्रेस से अलग हो गया तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी के सिर पर कितनी भी असफलताएं डाली जाएं लेकिन सच यही है कि वो ही कांग्रेस की आखिरी उम्मीद हैं। ऐसे ही मोदी इस समय देश की मजबूरी बन चुके हैं, क्योंकि उनसे बेहतर नेता इस समय देश में मौजूद नहीं है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो देश को एक स्थायी सरकार दे सकती है। जो लोग भाजपा या विपक्ष के कट्टर समर्थक हैं, वो क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग गुण-दोष के आधार पर अपना वोट डालते हैं, उनके सामने मोदी और भाजपा के अलावा क्या विकल्प है। राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूरी हैं लेकिन देश की मजबूरी नहीं हैं। देश की मजबूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं. उनसे ज्यादा विश्वसनीय और लोकप्रिय चेहरा इस समय भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। कांग्रेस की समस्या यह है कि उसके पास राहुल गांधी से ज्यादा विश्वसनीय और लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसे सामने रखकर वो पूरे देश में जनता से वोट मांग सकती है। समस्या यह है कि जनता राहुल गांधी के चेहरे पर वोट देने को तैयार नहीं है। भाजपा को ऐसी कोई समस्या नहीं है. जब भी मोदी राजनीति को अलविदा कहेंगे, तब भाजपा जिस भी चेहरे को आगे करेगी, उसे जनता का विश्वास मिल जाएगा। विपक्ष के लिए बड़ी समस्या यह है कि मोदी देश को अपना विकल्प देकर जाएंगे. वो इसके लिए नेताओं को तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस की समस्या नहीं हैं बल्कि वो पूरे विपक्ष की समस्या हैं क्योंकि उनके अलावा विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई और चेहरा नहीं है। वैसे तो विपक्ष किसी को भी प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकता है. इसके लिए उसके पास कई अच्छे नेता हैं। समस्या यह है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके नाम पर पूरे देश की जनता उसे वोट दे। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के अलावा अन्य सभी विपक्षी दल सिर्फ एक राज्य तक सीमित हैं। बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां एक से ज्यादा राज्यों में मौजूद हैं लेकिन ये दल इतने कमजोर हो चुके हैं कि विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकते। एक तरह से ये दल तो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस की कितनी भी आलोचना करे, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस उसकी मजबूरी है और कांग्रेस की मजबूरी राहुल गांधी हैं। विपक्ष के अन्य दल राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं इसलिए उनमें नेतृत्व की जंग जारी है। विपक्ष के बड़े नेताओं में ममता बनर्जी, स्टालिन और अखिलेश यादव का नाम लिया जा सकता है लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके नाम पर पूरे देश में विपक्ष वोट मांग सकता है। ये नेता अपने राज्यों में तो एक विश्वसनीय और लोकप्रिय चेहरा हैं लेकिन राज्य से बाहर निकलते ही इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। विपक्ष के नेताओं में आपसी संघर्ष भी इतना ज्यादा है कि कोई किसी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है।सवाल यह है कि इस विपक्ष पर देश की जनता कैसे भरोसा कर सकती है। अगर ये दल गठबंधन बनाकर कोई वादा करते हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, यह तय नहीं है। भारत की जनता में राजनीतिक जागरूकता और समझदारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसे बरगलाया नहीं जा सकता। 2024 का चुनाव लड़ने से पहले विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया था, आज वो कहां है। चुनाव के बाद इस गठबंधन की किसी बैठक की जानकारी नहीं है। इसके पदाधिकारी कौन है, इसका कार्यालय कहां है, कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ एनडीए लगातार मजबूत होता जा रहा है, भाजपा और इसके घटक दलों में गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीयता बन चुकी है और इससे छुटकारा पाना आसान होने वाला नहीं है।

राजद द्वारा कलाकारों पर ठीकरा फोड़ना हार के बाद नैतिक दिवालियापन का संकेत

सुजीत कुमार

पटना (अपना नालंदा)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि राजद की चुनावी रणनीति हमेशा से भीड़ और दिखावे पर आधारित रही है। चुनाव प्रचार के दौरान कलाकारों एवं लोकप्रिय गायकों के माध्यम से भीड़ जुटाकर माहौल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता ने इस दिखावे को नकार दिया। उनके अनुसार, बिहार की जागरूक जनता जुगाड़ की भीड़ या कृत्रिम लोकप्रियता से प्रभावित नहीं होती और विकास तथा नेतृत्व को आधार बनाकर फैसला करती है।

पटेल ने आरोप लगाया कि राजद ने चुनावी नतीजों के बाद अपने प्रचार में बुलाए गए कलाकारों को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया, जो न केवल कलाकारों का अपमान है बल्कि जनमत का भी अनादर है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों का मेहनताना तक न देना और फिर उन पर आरोप मढ़ना, राजद की पुरानी आदत और जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि भय, भ्रम और भीड़-आधारित राजनीति का फार्मूला जनता पहले ही समझ चुकी है। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि जनसमर्थन भीड़ से नहीं, कार्य और नीतियों से मिलता है। जनता अब तमाशे से नहीं, जवाबदेही और विकास से प्रभावित होती है।

पटेल ने कहा कि यह हार राजद के लिए केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक पराजय भी है। उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि भरोसा सम्मान, पारदर्शिता और विकास से बनता है—न कि कलाकारों को ढाल बनाकर और हार का ठीकरा उनके सिर फोड़कर।

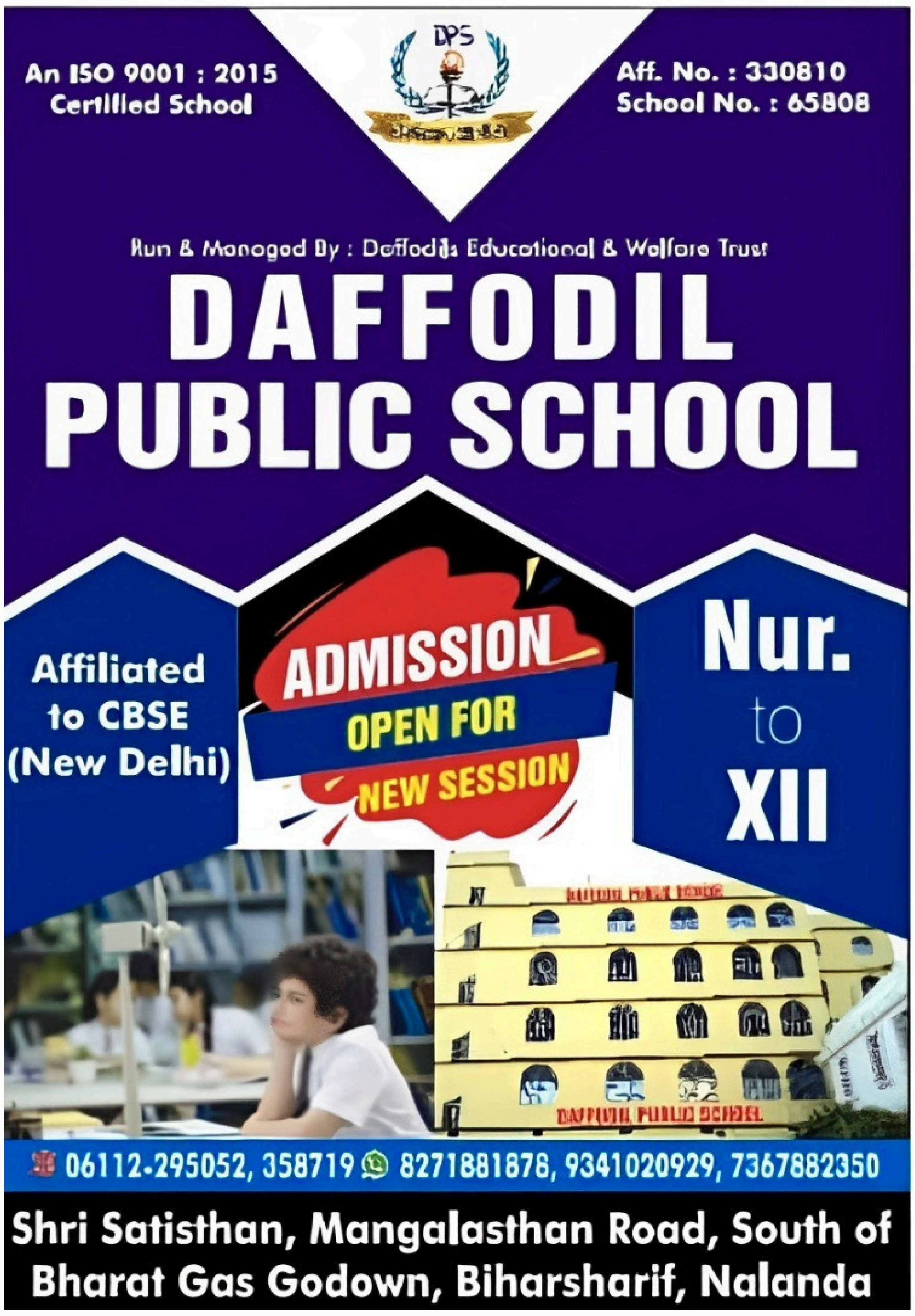

फतुहा-इस्लामपुर रेलखंड पर लेट लतीफी से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, उठी सुधार कि मांग

हिलसा (अपना नालंदा)। फतुहा-इस्लामपुर रेलखंड पर लगातार बिगड़ती परिचालन व्यवस्था को लेकर दैनिक रेल यात्री संघ के सदस्य गंभीर रूप से चिंतित हैं। संघ के टुनटुन यादव, सौरव कुमार, राज चंदन, सुधांशु कुमार, रजनीश रंजन और नीतीश निराला सहित कई अन्य सदस्यों ने बताया कि ट्रेनों की अनियमितता और लेट लतीफी ने यात्रियों की समस्याओं को बेहद बढ़ा दिया है।

यात्रियों का कहना है कि हिलसा स्टेशन पर कई प्रखंडों और पंचायतों के लोग निर्भर हैं, लेकिन सुविधाएं लगभग नदारद हैं। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टाइमिंग और सूचना प्रणाली लंबे समय से अव्यवस्थित है। स्टेशन के कायाकल्प की मांग वर्षों से लंबित है, जबकि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं।नियमित यात्रियों ने बताया कि पिछलेक माह से परिचालन स्थिति और बिगड़ गई है। कई ट्रेनों की निश्चित समय सारिणी ए समाप्त हो गई है। कई बार ट्रेनों को बिना स्पष्ट कारण छोटे स्टेशनों पर एक-एक घंटे तक रोक दिया जाता है, जिससे छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। पटना से इस्लामपुर तक मात्र 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में पैसेंजर ट्रेनों को पांच घंटे से अधिक समय लग रहा है। वहीं, फतुहा-हिलसा पैसेंजर ट्रेन को अक्सर रद्द कर दिया जाता है।यात्री संघ ने आरोप लगाया कि कोयला लदी मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने के कारण यात्री ट्रेनें अधिक लेट होती हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि वे डीआरएम और जीएम को एक्स (X) के माध्यम से स्थिति सुधारने की लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।उन्होंने रेल प्रशासन से ट्रेनों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने और हिलसा स्टेशन की सुविधाओं में शीघ्र सुधार करने की मांग की है।

एलआईसी हिलसा शाखा में वरिष्ठ अभिकर्ता सिया शरण आर्य के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

हिलसा (अपना नालंदा)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) हिलसा शाखा में सोमवार को वरिष्ठ अभिकर्ता स्वर्गीय सिया शरण आर्य के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। तीन दिनों पूर्व लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया था, जिससे एलआईसी परिवार में गहरा शोक व्याप्त है।कार्यक्रम में हिलसा शाखा के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विकास अधिकारियों और बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय सिया शरण आर्य के व्यक्तित्व, सौम्य व्यवहार, कार्यशैली और संस्था के प्रति उनके समर्पण को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि वे हमेशा ग्राहक सेवा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते थे। अभिकर्ता के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में एलआईसी की पहुंच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।शोक सभा के दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। सभी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस मौके पर विकास अधिकारी अफसर मतलूव ,संतोष कुमार सिन्हा, कौशल किशोर, अभिकर्ता शशांक शेखर उपाध्याय, पवन कुमार, संतोष कुमार, गौरव प्रकाश, राजेश कुमार सहित अनेक अभिकर्ता और कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि स्वर्गीय सिया शरण आर्य का योगदान सदैव याद रखा जाएगा।

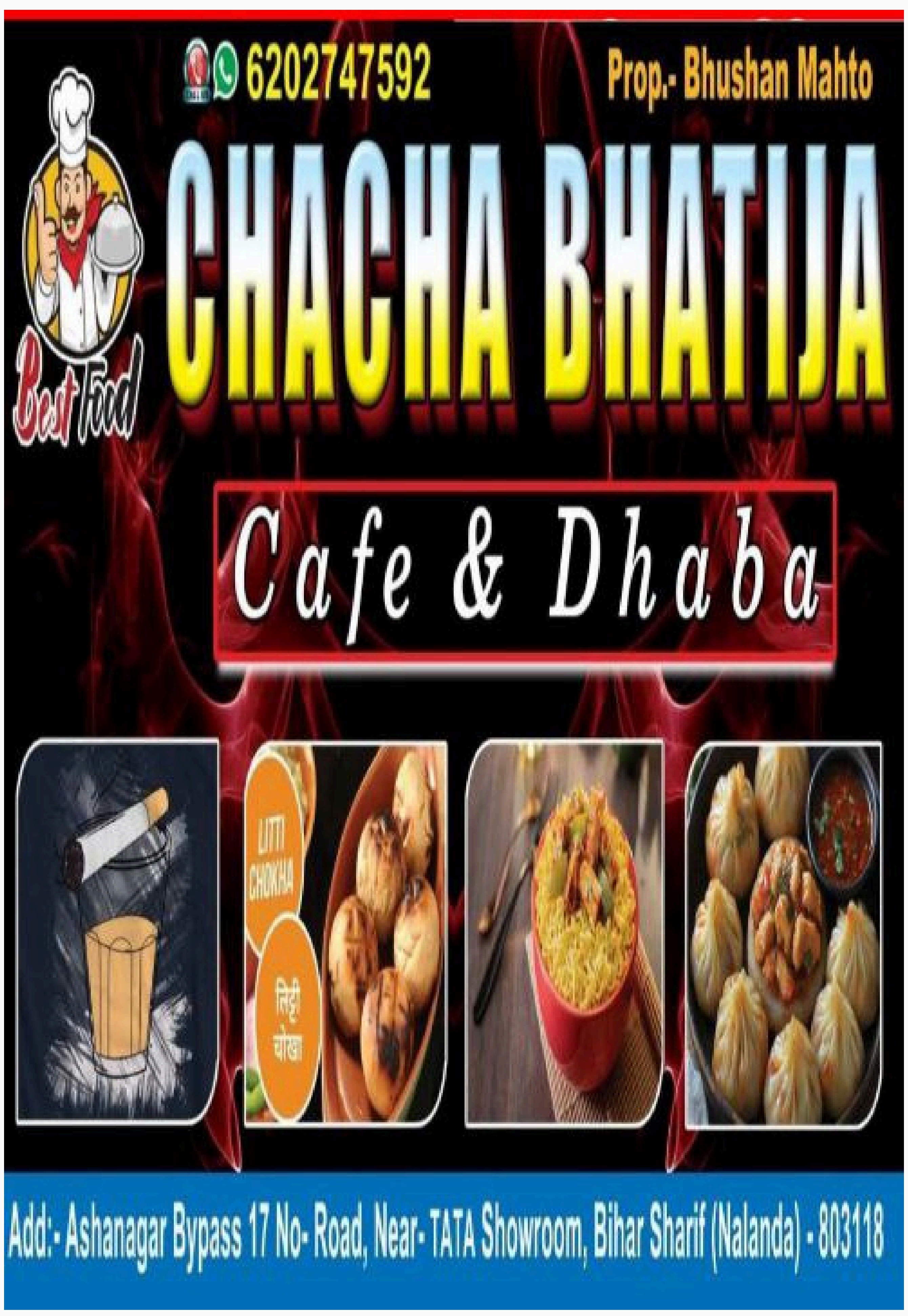

निभा इंस्टिट्यूट के शकीब और मेघा को लगातार दो सत्रों में मिला स्वर्ण पदक

राजगीर (अपना नालंदा)। राजगीर स्थित निभा इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने एक बार फिर स्वर्णिम उपलब्धि हासिल करते हुए लगातार दो शैक्षणिक सत्रों में गोल्ड मेडल प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में आयोजित नौवें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने संस्थान की दो प्रतिभाशाली बी.फार्म छात्राओं—शकीब अहमद राही और मेघा कुमारी—को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया।

शकीब अहमद राही ने सत्र 2020–24 में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की, जबकि मेघा कुमारी, जो राजगीर के इंद्रमोहन सिंह निराला की पुत्री हैं, ने सत्र 2021–25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोनों छात्राओं की सफलता से न केवल संस्थान का गौरव बढ़ा है, बल्कि राजगीर क्षेत्र की शैक्षणिक प्रतिष्ठा भी ऊंची हुई है।

संस्थान के सचिव डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने दोनों गोल्ड मेडलिस्ट को बधाई देते हुए कहा कि लगातार दो सत्रों में स्वर्ण पदक मिलना संस्थान की मजबूत शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और छात्रों की मेहनत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करेगी और संस्थान को फार्मेसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएगी।निभा इंस्टिट्यूट ने हाल के वर्षों में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं, अनुशासन और पेशेवर मार्गदर्शन के माध्यम से तेजी से अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। शकीब और मेघा की उपलब्धि से यह सिद्ध होता है कि संस्थान फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दे रहा है और आगे भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है।

पत्रकार मुकेश कुमार के पिता यमुना यादव के निधन पर हरनौत में शोक सभा

हरनौत (अपना नालंदा)। स्थानीय प्रखंड के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार के पिता दिवंगत यमुना यादव का सोमवार को पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। ब्रेन हेमरेज के कारण तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 11 नवंबर को पटना स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उपचार के क्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत का पार्थिव शरीर देर शाम उनके पैतृक गांव कोलावां लाया गया। मंगलवार को उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। लगभग 20 वर्षों तक दिवंगत यमुना यादव जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रूप में कार्यरत रहे थे और अपने सरल व्यवहार तथा सामाजिक जुड़ाव के कारण लोगों में सम्मानित थे।उनके निधन पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पीडीएस डीलरों, समाजसेवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सभी ने ईश्वर से पत्रकार मुकेश कुमार और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।इधर प्रखंड मुख्यालय स्थित राज्य खाद्य निगम टीपीडीएस गोदाम परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने शोक सभा आयोजित की। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि एसडीओ से मिलकर दिवंगत के आश्रित को पीडीएस दुकान का लाइसेंस जल्द उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी।शोक सभा में राजेश कुमार, सुनील कुमार उर्फ बब्लू कुमार, संजय कुमार, सुलेंद्र कुमार, बिंदेश्वर यादव, राजदेव पासवान, राजकुमार, सुनिल, अवधेश, विनोद, अखिलेश सहित कई लोग उपस्थित थे।

पॉक्सो कांड में दोषी आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, अदालत ने सुनाया कठोर फैसला

बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। नालंदा पुलिस की सक्रिय कार्रवाई, प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर बिहार थाना कांड संख्या 185/23 से जुड़े पॉक्सो मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। पुलिस द्वारा समर्पित चार्जशीट समय पर दाखिल की गई थी तथा विचारण के दौरान सभी गवाहों को उचित समय पर न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही, जब्त किए गए सभी प्रदर्शों और दस्तावेजों को विधिवत रूप से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूत हुआ।

सोमवार को एडीजे-04, बिहारशरीफ नालंदा की अदालत ने आरोपी राहुल कुमार उर्फ गोलू, पिता अशोक कुमार, निवासी बैगनाबाद, थाना बिहार, जिला नालंदा को दोषी करार दिया।

आरोपी पर धारा 366, 376(2) भादवि एवं 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। न्यायालय ने धारा 376(2) भादवि में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड, जबकि अर्थदंड न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

वहीं, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह फैसला समाज में संदेश देता है कि नाबालिगों से जुड़े गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई और कठोर दंड सुनिश्चित किए जाते रहेंगे।

हरनौत के सिरसी गांव में सड़क निर्माण अनियमितता पर डीएम ने बनाई टीम

संजय कुमार

बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के सिरसी गांव में सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितता के आरोप सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि ढीली मिट्टी पर मात्र आधा इंच तारकोल बिछाकर सड़क का निर्माण किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रही स्थिति से यह आशंका गहराती है कि निर्माण कार्य में संवेदक और संबंधित अभियंताओं द्वारा मानकों की खुली अवहेलना की गई है। मामला गंभीर होने के कारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए त्रिसदसीय जांच दल का गठन कर दिया है।गठित टीम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी नालंदा मनोहर कुमार साहु, पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता शिवनाथ राम को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि टीम पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर स्थल निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।डीएम ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच में लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीणों ने डीएम की त्वरित पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।

आईआईटी पटना द्वारा पुल सेफ्टी ऑडिट शुरू, यातायात रहेगा नियंत्रित

अखिलेंद्र कुमार

बिहारशरीफ (अपना नालंदा)। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल नालंदा की ओर से यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार द्वारा लागू ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी महत्वपूर्ण पुलों का प्रथम चरण का सेफ्टी ऑडिट 24 नवंबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत आईआईटी पटना के विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम तथा बीआरपीएनएनएल के अनुभवी पुल विशेषज्ञ आधुनिक मशीनों की सहायता से पुलों की संरचनात्मक मजबूती, सुरक्षा मानकों, तकनीकी खामियों और संभावित जोखिमों की विस्तृत जांच करेगी।

जांच के दौरान आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संबंधित पुलों पर यातायात को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित, प्रतिबंधित या मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया कुछ समय के लिए असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह कदम पुलों की सुरक्षा और भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।इस कार्य को सुचारु और सुरक्षित रूप से पूरा कराने के लिए जिला पदाधिकारी नालंदा और पुलिस अधीक्षक नालंदा द्वारा दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा आवश्यक पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर स्थल पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था बनाए रखें और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करें, ताकि जांच कार्य बिना किसी व्यवधान के समय पर पूरा किया जा सके।इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए श्री रूप नारायण शर्मा, वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल नालंदा को वरीय प्रभार सौंपा गया है। उनके सहयोग के लिए परियोजना अभियंता श्री वीर बहादुर सिंह को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि वे सेफ्टी ऑडिट के दौरान जारी यातायात निर्देशों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

हरनौत में रबी सत्र हेतु निबंधित किसानों को मिल रहा गेहूं बीज

हरनौत (अपना नालंदा)। प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन में रबी फसल के लिए गेहूं बीज वितरण पुनः शुरू हो गया है। बीएओ ब्रजकिशोर चरण ने बताया कि प्रखंड में इस वर्ष लगभग 6,500 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 410 क्विंटल गेहूं बीज उपलब्ध कराया गया था, जिसे पूरी तरह किसानों के बीच वितरित किया जा चुका है।

दूसरे चरण में 210 क्विंटल गेहूं बीज प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण वर्तमान में किया जा रहा है। इससे किसानों में संतोष देखा जा रहा है क्योंकि समय पर बीज मिलने से बुवाई कार्य प्रभावित नहीं होगा। बीएओ ने बताया कि सभी निबंधित किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिन किसानों को अब तक बीज नहीं मिल पाया है, उन्हें भी उपलब्धता के अनुसार बीज दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि कोई भी वंचित किसान ई-किसान भवन पहुंचकर अपनी सुविधा के अनुसार रबी फसल का बीज प्राप्त कर सकता है। कृषि विभाग द्वारा किसानों की सहायता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जिले में रबी सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

बारात से लौटते युवक की फोर व्हीलर नहर में पलटने से मौत

मोहम्मद जियाउद्दीन

इस्लामपुर (अपना नालंदा)। समाजसेवी एवं वहीदुद्दीन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इकरा इंग्लिश अकादमी के सचिव और पूर्व दफादार सैय्यद शाह अनवारुल हक का हृदयगति रुक जाने से अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

जनाजे की नमाज इस्लामपुर के बुढ़ा नगर स्थित जामा मस्जिद के पास अदा की गई, जहाँ सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा के लिए दुआएँ मांगीं। नमाजे जनाजा जामा मस्जिद के इमाम हाफिज कारी अरशद मदनी ने अदा कराई और उनकी मगफिरत की दुआ की। अंतिम संस्कार बुढ़ा नगर पुरानी दर्सगाह स्थित रूहे कब्रिस्तान में किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, शुभचिंतक और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सभी ने उनके निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया।इस दुखद मौके पर राशिद अनवर, खालिद अनवर, परवेज आलम, सैय्यद अनवर मुजीब, अधिवक्ता एजाज अहमद, तनवीर आलम सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और सम्मानित नागरिक मौजूद थे।सभी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सैय्यद शाह अनवारुल हक हमेशा शिक्षा, सामाजिक कार्य और मानव सेवा के लिए समर्पित रहे। उनके जाने से समाज ने एक सच्चा सेवक और मिलनसार व्यक्तित्व खो दिया है।

घीमोय गांव चोरी कांड में पुलिस ने दो बालक को किया निरुद्ध

हरनौत (अपना नालंदा)। गोखलपुर थाना पुलिस ने सोमवार को चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो बालकों को निरुद्ध किया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बीते 22 नवंबर को घीमोय गांव निवासी छोटे महतो नोनिया के घर में देर रात अज्ञात चोरों ने घुसकर नकदी और मोबाइल फोन की चोरी कर ली थी। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कांड संख्या 75/25 दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संभावित आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 24 घंटे के भीतर छापेमारी कर चोरी किए गए मोबाइल फोन तथा 1,900 रुपये नकद बरामद कर लिए। बरामदगी के बाद जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए दोनों बालक नाबालिग हैं, इसलिए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में लगातार गश्ती बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत की भावना देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि ऐसे कदमों से क्षेत्र में अपराध पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

www.apnanalanda.com

अपना नालन्दा

अपना शहर, अपना खबर

नालन्दा का नंबर 1 अखबार

अपना नालन्दा में विज्ञापन देकर
अपने व्यवसाय को दे नई पहचान

नालन्दा की जनता की आवाज

अपने क्षेत्र की खबर भेजने
ओर विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।

9031468165
9608311251

नालंदा जिले के सभी प्रखंडों में संवाददाता सह विज्ञापन प्रतिनिधि कि आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति 9031468165 पर संपर्क करें।